

अध्याय - 18

श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

परिचय

18.1 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी वी जी एन एल आई) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय जुलाई (1974 में स्थापित) श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान है।

लक्ष्य तथा अधिदेश

18.2 संस्थान के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की बहिर्नियमावली में उन क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से बताया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक जो है निम्नवत् हैं:-

- प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार तथा कार्यशाला आयोजित करना तथा उसमें सहायता प्रदान करना।
- अपने आप तथा अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान आयोजित करना, उसमें सहायता प्रदान करना तथा समन्वय करना।
- निम्न के लिए स्कन्ध स्थापित करना:
 - शिक्षा प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास;
 - कार्यात्मक अनुसंधान सहित अनुसंधान
 - परामर्श और
 - प्रकाशन तथा संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रकाशन तथा अन्य ऐसे कार्य जो आवश्यक हों।
- श्रम तथा सहायक कार्यक्रमों के नियोजन तथा कार्यान्वयन में सामने आई विशेष समस्याओं का विश्लेषण तथा उनके निवारण के उपाय सुझाना।
- पुस्तकालय तथा सूचना सेवाएं स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना।
- भारत में तथा भारत से बाहर समान उद्देश्यों वाले अन्य संस्थानों तथा अभिकरणों से सहयोग

संरचना

18.3 संस्थान की शीर्ष शासी निकाय सामान्य परिषद, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, संस्थान के कार्य करने की विस्तृत योजना के मापदंड निर्धारित करती है। श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद संस्थान के क्रियाकलापों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करती है। सामान्य परिषद तथा कार्यकारी परिषद दोनों त्रिपक्षीय होती हैं तथा इसके सदस्य सरकार, श्रमिक संघ परिसंघ, नियोक्ता संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा श्रम के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वान तथा विशेषज्ञ होते हैं। संस्थान का निदेशक मुख्य कार्यपालक होता है तथा प्रबंध तथा प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 व्यवसायिकों से संगठित संकाय द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों में निदेशक को सहयोग प्रदान किया जाता है तथा प्रशासनिक स्टाफ द्वारा सहायता की जाती है।

धन-व्यवस्था

18.4 वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार ने निम्नानुसार सहायता अनुदान स्वीकृत किया:

गैर योजना	180.00 लाख रुपए
योजना	278.00 लाख रुपए

संस्थान ने अपने आन्तरिक संसाधनों से वार्षिक 91.68 लाख रुपये जुटाए जिसमें से 64.42 लाख रुपये सरकार के अनुमोदन के पश्चात् विधिवत् सृजित कायिक निधि में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वर्तमान वर्ष (2005-2006) के दौरान स्वीकृत राशि इस प्रकार है:

श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

गैर योजना	200.00 लाख रुपए
योजना	310.00 लाख रुपए

मुख्य क्रियाकलाप

जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के खुर्जा प्रखंड में एक कार्रवाई अनुसंधान परियोजना।

अनुसंधान

श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र

18.5 संस्थान के क्रियाकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। अनुसंधान के विषय में संगठित और असंगठित क्षेत्र संबंधी श्रम समस्याओं के व्यापक आयाम शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रम संबंधी समस्याओं और मुद्दों के विश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है जैसे बंधुआ मजदूर, कामकाजी बच्चे, महिला श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि। ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करता है ताकि ग्रामीण श्रमिकों का संगठित करने के संभावित तरीकों और उपायों का पता लगाया जा सके।

- श्रम पर निजीकरण का प्रभाव : बाल्को विनिवेश विनिवेश का एक अध्ययन
- अरूणाचल प्रदेश में ग्रामीण और कृषि रोजगार वृद्धि, संघटन और अवधारणा
- वैश्वीकृत जगत में श्रमिक संघवाद और सामाजिक चुनौतियां रोजगार संबद्ध और विनियम केन्द्र

पूर्ण की गई परियोजनाएं

पूर्ण तथा चालू अनुसंधान परियोजनाएं

- निजी स्कूलों में श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे: नोएडा का एक मामला अध्ययन

18.6 संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं तथा चालू अनुसंधान परियोजनाओं की सूची निम्नांकित है:

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम पूर्ण की गई परियोजनाएं

कृषिक संबंधों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए केन्द्र

- भारतीय श्रम आंदोलन का मौलिक इतिहास- III
- तमिलनाडु में श्रम इतिहास के दस्तावेजी स्रोतों का संकलन – III
- भारतीय मजदूर संघ के इतिहास का प्रलेखन
- पश्चिम बंगाल के 24 परगना (दक्षिण) के समुदाय-आधारित परिधान उद्योग की मौजूदा और विगत स्थिति
- चमडा दस्तकारों से ईट भट्ठा कामगारों तक : निडाल यात्रियों का वृतांत
- कोयला कामगारों की आउटसोर्सिंग का प्रभाव: एक मौखिक इतिवृत्ति
- भारतीय खेत मजदूर संघ-परिसंघ के रिकार्डों/सामग्रियों का प्रलेखन और संकलन

चल रही परियोजनाएं

चल रही परियोजनाएं

- शहरी औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और कमाई-अरूणाचल प्रदेश का एक अध्ययन
- गुवाहाटी शहर के निर्माण कामगार रोजगार, रोजगारपरकता और सामाजिक सुरक्षा
- रोजगार संभाव्यता का संकलन —पश्चिम बंगाल का एक मामला अध्ययन
- लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि हेतु कल्याण उपायों का एक अध्ययन
- कृषिक ढांचा, सामाजिक संबंध और कृषि विकास: राजस्थान के गंगानगर और जोधपुर जिलों का एक मामला अध्ययन।
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का आकलन तथा लाभभोगियों की प्रभावी भागीदारी का संवर्धन: टीकमगढ़ा, मध्य प्रदेश में एक कार्रवाई अनुसंधान परियोजना; और
- सामाजिक सुरक्षा उपायों का आकलन तथा लाभभोगियों की प्रभावी भागीदारी का संवर्धन:

- महाराष्ट्र में जाति आंदोलन और कामकाजी वर्ग के संबंध में बातचीत के बारे में अनुसंधान तथा दस्तावेजों का संकलन

- भारतीय श्रमिक संघों के केन्द्र से संबंधित दस्तावेजों का संकलन
- श्रम कानून बनाना तथा सामूहिक सौदेकारिता परम्पराएं: मुम्बई में कामकाजी कर्मचारी संघ तथा स्वतंत्र श्रमिक संघ आंदोलन
- अहमदाबाद शहर के बीड़ी कामगारों के सोर्स मैटिरियल और डिजीटिल कलेक्शन का आयोजन
- 1985 से एक केन्द्रीय विधान के लिए निर्माण कामगारों के राष्ट्रीय अभियान के दस्तावेज का अध्ययन और संकलन

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं

चल रही शोध परियोजनाएं

- बाल श्रम की मांग के बारे में तकनीकी परिवर्तन और उद्योग पुनर्गठन के संबंध में उद्योग का अध्ययन

श्रम और स्वास्थ्य केन्द्र

चल रही परियोजनाएं

- कार्यजगत में एच आई वी/एड्स का निवारण: एक त्रिपक्षीय प्रत्युत्तर — फेज- II भाग- II
- कामगारों के अनौपचारिक नियोजन में स्वास्थ्य असुरक्षा: मौजूदा और संभावित हस्तक्षेपों का अध्ययन

स्त्री/पुरुष और श्रम केन्द्र

चल रही परियोजनाएं

- वैश्वीकरण और महिला कार्य में एन एस एस ओ आंकड़े के विश्लेषण को अलग करना
- प्रवासी महिलाएं और मजदूरी रोजगार: दिल्ली में स्वास्थ्य देखरेख व्यवसायिकों के बीच कार्य एवं पहचान के मुद्दों का पता लगाना

प्रशिक्षण तथा शिक्षा

18.7 श्रम संबंधी विभिन्न आयामों से जुड़े भिन्न-भिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना संस्थान का एक मुख्य कार्य है। निम्नांकित लक्षित समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

- केन्द्र तथा राज्य सरकार के श्रम प्रशासक
- औद्योगिक संबंध प्रबंधन

- संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक संघ नेता
- बाल श्रम उन्मूलन से जुड़े भागीदार
- पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधि
- श्रम अध्ययन संबंधी अनुसंधानकर्ता

18.8 संस्थान द्वारा अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2005 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे सारणी 19.1 में दिए गए हैं और नवम्बर, 2005 से अप्रैल, 2006 के दौरान आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे सारणी — 19.2 में दिए गए हैं।

18.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कई नई पहलें की गयीं। इन पहलों में से मुख्य निम्नांकित हैं:-

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में राज्य श्रम संस्थानों/अन्य संस्थानों के साथ

नेटवर्किंग

18.10 संस्थान में श्रम बाजार में क्षेत्रगत और सेक्टरगत असमानताओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए समग्र श्रम समस्या के समुचित समाधान के उद्देश्य से राज्य श्रम संस्थानों, सी बी डब्ल्यू ई, श्रम ब्यूरो तथा समान उद्देश्य वाले अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को सांस्थानिक रूप देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

18.11 इसके मद्देनजर संस्थान महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, राज्य श्रम संस्थान उड़ीसा; तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान के साथ मिलकर श्रम कानून प्रवर्तन, बाल श्रम सेवाओं के समेकन आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर बल

18.12 इस बात के साक्ष्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि एच आई वी/एड्स के प्रसार का कार्यस्थल पर खासा असर पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सामाजिक भागीदारों की व्यापक सहभागिता की कार्यनीति तैयार करने के लिए संस्थान ने श्रमिक संघ नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सामाजिक भागीदारों आदि जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के लिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर बल

18.13 संस्थान ने बाल श्रम, नेतृत्व विकास तथा ग्रामीण श्रम के क्षेत्र में स्रोत व्यक्तियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की पहल की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्रोत व्यक्तियों को तैयार करना है जो आगे चलकर अपने कैडर को प्रशिक्षण दे सकें ताकि प्रभाव बहुगुणित हो सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशिष्ट कार्यक्रम

18.14 संस्थान इन कार्यक्रमों को बहुत महत्व देता है क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, इस इलाके में कोई बड़ा संगठित प्रयास नहीं किया गया है। संस्थान ने इन कार्यक्रमों को प्रशिक्षण कार्यसूची में हर वर्ष शामिल करने का निर्णय लिया है। वर्ष के दौरान संस्थान ने 15 कार्यक्रमों की योजना बनाई है जिनमें से 9 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 247 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शेष 6 कार्यक्रम दिसम्बर, 2005 से मार्च, 2006 के दौरान आयोजित किए जायेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

18.15 यह संस्थान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है जो मंत्रालय के आई टी ई सी/एस सी ए ए पी कार्यक्रमों के तहत है। इस वर्ष संस्थान ने निम्नांकित दो कार्यक्रमों का आयोजन किया/करेगा-

- संस्थान के परिसर में 12 से 30 सितम्बर, 2005 तक आई टी ई सी/एस सी ए ए पी के तहत विश्व अर्थव्यवस्था में श्रम प्रशासन तथा रोजगार संबंध ।
- 17 से 28 अक्टूबर, 2005 तक प्रशासकों के लिए नेतृत्व विकास
- एच आई वी/एड्स की रोकथाम 21 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2005 तक

18-16 उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अलावा संस्थान ने वैश्विक श्रम इतिहास पर कार्यशाला का आयोजन 10-12 नवम्बर, 2005 तक भारतीय श्रम इतिहासकारों के सहभागिता से किया।

श्रम तथा विकास में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

18.17 खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रम बल को शिक्षित करना संस्थान के मुख्य लक्ष्यों में से है। इस

लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संस्थान ने इग्नू के साथ मिलकर विकास में श्रम विषयक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम मजदूरों और खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम संबंधी मुख्य विषयों के प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें शैक्षिक रूप से सशक्त करना है। इस कार्यक्रम के लिए प्राप्तकर्ता/शिक्षार्थी समूहों में श्रमिक संघ कार्यकर्ता और नेता, गैर-सरकारी संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी, जिला विकास एजेंसियाँ, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण शिक्षा प्रदाता तथा ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो आयोजक/शिक्षा प्रदाता बनने के इच्छुक हैं। पाठ्यक्रम की शुरुआत जुलाई, 2000 से हो चुकी है। अब तक इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में 521 प्रतिभागियों ने अपना नाम दर्ज कराया है।

कार्यशालायें तथा संगोष्ठियाँ

18.18 कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों के आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दिसम्बर, 2004 तक राष्ट्रीय स्तर की छह बड़ी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। शेष अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित 4/5 कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन का अनुमान है।

प्रकाशन

18.19 श्रम संबंधी विभिन्न सूचनाओं तथा खासतौर से संस्थान के शोध संबंधी निष्कर्षों का प्रसार संस्थान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संस्थान ने अपने नियमित तथा अवसरगत प्रकाशनों के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना जारी रखा।

नियमित प्रकाशन

- श्रम और विकास- श्रम और विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित द्वि-वार्षिक पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धान्तिक विश्लेषण तथा गहन पड़ताल के जरिए श्रम संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति समझ को बेहतर बनाने को समर्पित है। इस पत्रिका में श्रम और श्रम संबंधी क्षेत्रों से जुड़ी विद्वतापूर्ण रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है जिनमें सामाजिक आर्थिक, ऐतिहासिक तथा कानूनी पहलुओं के अलावा शोधपरक नोट तथा पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन भी किया जाता है- खासकर विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में ।

- अवार्ड्स डाइजेस्ट- इस मासिक पत्रिका में श्रम और औद्योगिक संबंध विषयक नवीनतम मामला कानूनों का सार प्रकाशित किया जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनलों द्वारा दिये गये निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं।
- श्रम विधान- इस हिन्दी पाक्षिक में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा कैट मामलों का सार प्रकाशित किया जाता है।

एन एल आई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

18.20 संस्थान के शोध संबंधी निष्कर्षों का प्रसार मुख्यतः एन एल आई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के जरिए किया जाता है। अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2005 की अवधि के दौरान एन एल आई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशन को सारणी 18.3 में दिया गया है।

प्रेस में एन एल आई अनुसंधान अध्ययन

- चैलेंजेज विफोर दि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन दि ग्लोबलाइज्ड इरा: ए स्टडी आन इंडियन कान्टेक्टर
- आर्गनाइजिंग रुरल लेबर : केस ऑफ चित्तौडगढ़, राजस्थान
- ट्रेड लिबरलाइजेशन ऐंड इंडियन एग्रीकल्चर: ए डिसकसन ऑन फूड सिक्युरटी कन्सर्न्स इन डब्ल्यू टी ओ रीजीक

अन्य प्रकाशन

- प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर 2005-2006 (द्विभाषी)
- वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 (हिन्दी और अंग्रेजी)

श्रम मंत्रालय की ओर से प्रकाशन

18.21 संस्थान ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से निम्नांकित का प्रकाशन भी किया है:-

श्रम समाचार - श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम और रोजगार

मंत्रालय की इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। इसमें श्रम संबंधी आलेख तथा समाचार प्रसारित किए जाते हैं। यह पत्रिका श्रमिकों और नियोक्ताओं के समग्र हित में सूचनाओं के प्रसार का एक माध्यम है। पत्रिका का पहला अंक महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जन्म शताब्दी के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2002 को प्रकाशित किया गया था। इसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। फिलहाल इस पत्रिका का प्रकाशन संस्थान द्वारा मासिक रूप से किया जाता है। अगस्त, 2004 से श्रम समाचार का अंग्रेजी में भी प्रकाशन किया जा रहा है।

श्रम सूचना संबंधी एन आर डी रिसोर्स सेंटर

18.22 एन आर डी सी एल आई श्रम अध्ययन के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केन्द्र है। दिनांक 1 जुलाई, 1999 को संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर केन्द्र को संस्थान के संस्थापक डीन श्री नीतिश आर.डे. की स्मृति में पुनर्नामित किया गया। अब यह केन्द्र पूर्ण कम्प्यूटरीकृत है और अपने प्रयोक्ताओं को निम्नांकित सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है।

सेवाएं:

- चुनिंदा सूचना का प्रसार (एस डी आई)
- नवीनतम जानकारी सेवा
- ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं
- आनलाइन खोज
- पत्रिकाओं के आलेखों को सूचीबद्ध करना
- समाचार पत्रों के लेख की क्लिपिंग
- रि-प्रोग्राफिक सेवा
- सी डी रोम सर्च
- श्रव्य/दृश्य सेवा
- करैन्ट कन्टेंट सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- प्रदानकारी सेवा

उत्पाद

- गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर- आंतरिक त्रैमासिक पत्रिका जिसमें 85 चुनिंदा पत्रिकाओं के आलेखों की ग्रंथ सूची संबंधी सूचना होती है।

- करेंट अवेयरनेस बुलेटिन-आंतरिक त्रैमासिक पत्रिका जिसमें एन आर डी आर सी एल आई के अधिग्रहण संबंधी सूचना की ग्रंथ सूची होती है।
- न्यूज पेपर आर्टिकल क्लिपिंग- मासिक प्रकाशन जिसमें मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में छपी रचनाओं संबंधी सूचना ग्रंथ रूप में होती हैं।
- आर्टिकल एलर्ट- साप्ताहिक प्रकाशन जिसमें चुनिन्दा पत्रिकाओं में छपी रचनाओं संबंधी सूचना ग्रंथ रूप में होती है।
- करेंट कन्टेंट सर्विस- मासिक प्रकाशन । इसमें खरीदी गई पत्रिकाओं के उपयुक्त पृष्ठों का संकलन होता है।
- एन आर डी आर सी एल आई का बाल श्रम के बारे में अलग से प्रलेखन केन्द्र भी है।

18.23 एन आर डी आर सी एल आई ने अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2005 के दौरान 239 पुस्तकों/रिपोर्टों आदि का स्टाक बढ़कर 52576 हो गया । इसके अलावा, प्रलेखन केन्द्र नियमित रूप में 234 व्यावसायिक पत्रिकाओं/मैगजीनों की खरीद करता है।

सारणी 18.1

संस्थान द्वारा अप्रैल, 2005 से नवम्बर, 2006 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	11	84	215
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	10	42	244
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	23	130	690
4.	बाल श्रम कार्यक्रम	18	70	517
5.	अनुसंधान प्रणाली कार्यक्रम	02	26	48
6.	स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम	11	27	355
7.	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	04	46	72
8.	सहयोगकारी कार्यक्रम	02	08	62
	योग	81	433	2203

दिसम्बर, 2004 से मार्च 2005 के दौरान प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	दिनों की संख्या
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	06	58
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	03	15
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	10	64
4.	बाल श्रम कार्यक्रम	04	15
5.	स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम	02	09
6.	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	01	14
7.	सहयोगकारी कार्यक्रम	02	04
	योग	28	179

सीरीज नं.	अनुसंधान अध्ययन शृंखला
034/2004	तमिलनाडु के चाय बागानों में ठंका संबंधी व्यवस्थाएं
054/2004	शहरी औपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम : नोएडा में रैगपिकर्स का एक अध्ययन
056/2004	भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का आकार संघटक और विशेषताएं
057/2004	ईट भट्टा कामगार श्रम प्रक्रिया और प्रवास का एक अध्ययन
058/2004	ऐन्टी-तम्बाकू का प्रभाव- बीड़ी लपेटने वालों, तम्बाकू कृषकों और तेंदू पत्ता एकत्र करने वालों की जीविका के बारे में विधान
059/2004	कौशल विकास प्रणाली : एक सूक्ष्म स्तर साक्ष्य
060/2004	उत्तर दक्षिण संबंधों के संदर्भ में श्रम का स्वरूप और अंतरराष्ट्रीय श्रम प्रवाह एक सिंहावलोकन
062/2005	प्रवास और एच आई वी/एड्स की संवेदनशीलता व्यावहारिक हस्तक्षेप रणनीतियां विकसित करना
063/2005	श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण : एन सी एल पी स्कूलों और एम ए वाई ए का एक मामला अध्ययन